B.A. Part 2
Paper IV Fn

24.8.20

संतुलित बजट और इसके पक्ष में तर्क :-

(Balanced budget & arguments for balanced budget)

(Balanced Budget)

संतुलित बजट

* अर्थ (Meaning)

बजटीय संतुलन, अधिशेष और घाटे की अवधारणाओं को बजटीय 'व्यय' और ~~स्तर~~ 'राजस्व प्राप्तियों' के आपसी अंतर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अर्थात् यदि विचाराधीन राजकोषिय वर्ष में बजटीय 'व्यय' इसकी '~~स्त~~ 'राजस्व प्राप्तियों'

- के बराबर हो तो यह बजटीय संतुलन की स्थिति है;
- से अधिक हो तो यह बजटीय घाटे की स्थिति है;
- से कम हो तो यह बजटीय अधिशेष की स्थिति है।

परंतु इन साधारण-सी दिखने वाली परिभाषाओं में वास्तविक समस्या ~~का~~ यह तय करना है कि लोक बजट के

- बजटीय संवितरणों (disbursements, or payments or outgoings) में से कौन-सी मदें बजटीय 'व्यय' हैं तथा
- बजटीय प्राप्तियों में कौन-सी मदें ~~सत~~ ~~स्तर~~ 'राजस्व' हैं।

इसके अतिरिक्त आर्थिक और नीति दृष्टिकोण से बजटीय प्राप्तियों और संवितरणों के कुछ खण्डों के आपसी अंतरों के आधार पर बजटीय 'घाटे' के कुछ ऐसे अनुमान भी परिभाषित किए ~~म~~ जाते हैं जिन्हें विश्लेषणात्मक और नीति उद्देश्यों के दृष्टिकोण से उपयोगी समझा जाता है। इन अनुमानों की विस्तृत व्याख्या एक अलग परिशिष्ट में की गई है। परंतु यह तथ्य स्वस्पष्ट है कि इन परिभाषाओं के प्रदत्त अर्थ इनमें प्रयुक्त संवितरणों और प्राप्तियों के खण्डों में सम्मिलित मदों पर निर्भर ~~करता~~ करते हैं। उदाहरणार्थ सार्वजनिक ऋणों के मूलधन की प्राप्तियों और भुगतानों को पूँजी खाते में रखा जाता है, अतः इनका प्रयोग 'पूंजी खाते के घाटे' के अनुमान में किया जाता है। इसके विपरीत ब्याज की अदायगियों और प्राप्तियाँ राजस्व खाते में दर्शाई जाती हैं, अत: वे '~~स्त~~ राजस्व खाते का घाटा' अनुमान करने में प्रयुक्त होती हैं। यह भी स्वस्पष्ट है कि संवितरणों

Scanned by CamScanner

और प्राप्तियों की कई मदों के वर्गीकरण पर मतभेद भी संभव है। उदाहरणार्थ यदि सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर अपने व्यय का वित्त-पोषण करे, तो इन प्राप्तियों के वर्गीकरण पर मतभेद हो सकता है।

* संतुलित बजट के पक्ष में तर्क (Arguments for a Balanced Budget)

• परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार सरकार की चेष्टा यह रहनी चाहिए कि बजट सदैव संतुलित रहे। जिस प्रकार एक निजी आर्थिक इकाई के लिए उधार लेकर व्यय करना आर्थिक दृष्टि से घातक हो सकता है, इसी प्रकार सार्वजनिक बजट में भी लगातार घाटे पर चलने का कोई औचित्य नहीं बनता। इस दृष्टिकोण के पीछे लोगों की यह धारणा निहित है कि सरकारों में बहुधा अनावश्यक और फालतू व्यय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए की प्रभावी विधी यही है कि सरकार अपने व्यय को अपनी राजस्व प्राप्तियों तक ही सीमित रखने को बाध्य हो।

• घाटे के बजट से साख और मुद्रा में वृद्धि होने के कारण मुद्रा स्फीति होती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं।

• घाटे के बजट से होने वाली कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार का व्यय और भी बढ़ जाता है जिससे घाटे के बजट से छुटकारा पाना अति कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त उधार लेने के कारण सार्वजनिक ऋण में भी लागतार वृद्धि होती रहती है। इससे भी सरकार पर ब्याज और मूलधन चुकाने का बोझ बढ़ता जाता है। फलस्वरूप एक ओर सरकार को नया उधार लेने को विवश होना पड़ता है तथा दूसरी ओर इसके राजस्व का एक बढ़ता भाग 'ऋण-सेवा' में खप जाता है जिससे अन्य व्यय-मदों के लिए संसाधनों की कमी पड़ने लगती है।

• करदाताओं को कर अदा करना अच्छा नहीं लगता और वे इसका विरोध करते हैं। इसलिए यदि सरकार को उधार लेने की मनाही हो, तो इसे मजबूर होकर अपव्यय रोकना पड़ता है। इस प्रकार संसाधनों के सदुपयोग में सहायता मिलती है।

• कुछ लोगों का यह मत है कि घाटे के बजट से आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायता मिलती है। परंतु इस तर्क के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को घाटे की व्यवस्था का सहारा

Scanned by CamScanner

होने की आवश्यकता नही हैं, विशेषकार जब हमारे पास मंदी से जूझने के लिए कई अन्य उपयोगी राजकोषीय यंत्र उपलब्ध हैं तथा जब बढ़ते सार्वजनिक ऋण के परिणाम भविष्य में काफी हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ सरकार मंदी को दूर करने हेतु अपने बजट को संतुलित रखते हुए सार्वजनिक व्यय को बढ़ा सकती है।

Scanned by CamScanner